



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2665/2015

Gumanaram S/o Rambaxaram, R/o Bhichari Ka Bass, Tehsil Nawa, District Nagore, at present village Khooor, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar (Raj.).

----Appellant

Versus

1. Bhawarlal S/o Jeewanram, R/o Post Nalot, Tehsil Nawa, District Nagore (Raj.) (Registered owner tractor No. RJ 37 RA 2280).
2. The New India Insurance Company Ltd., through branch office Director, oppo Court, Jalan Bhawan, Sikar (Raj.) (Insurance Company tractor No. RJ 37 RA 2280)

----Respondents

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1832/2015

The New India Insurance Company Ltd., having its Registered & Head Office at 87, Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai 40001 and having its Regional Office at Second Floor, South Block, Nehru Place Tonk Road, Jaipur, through its Constituent Attorney.

----Appellant

Versus

1. Gumanaram S/o Rambaxaram, R/o Bhichari Ka Bass, Tehsil Nawa, District Nagore, at present village Khooor, Tehsil Dantaramgarh, District Sikar (Raj.).
2. Bhawarlal S/o Jeewanram, R/o Post Nalot, Tehsil Nawa, District Nagore (Raj.).

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Akshat Chaudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Nishtha Jain, Adv. for Mr. Sanjay Singhal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

27/02/2026

विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, सीकर द्वारा प्रकरण W.C.C./N.F. No. 21/2010 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2015 से व्यथित होकर धारा 30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे



“अधिनियम-1923” कहा जावेगा) के तहत दावेदारों की ओर से प्रतिकर राशि में बढ़ोतरी हेतु अपील संख्या 2665/2015 तथा अवार्ड को अपास्त किये जाने हेतु अपीलार्थी-बीमा कम्पनी की ओर से अपील संख्या 1832/2015 प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त दोनों अपील एक ही निर्णय से संबंधित होकर एक ही आदेश के माध्यम से निस्तारित की जा रही हैं।

अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से आवेदक/आहत गुमानाराम के पक्ष में 2,91,475/- रुपये प्रतिकर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित नियोजक-प्रत्यर्थी क्रम 1 तथा अपीलार्थी-बीमा कम्पनी से दिलाये जाने का आदेश दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता दावेदार का निवेदन है कि प्रतिकर राशि की गणना करते समय आहत की आय को समुचित रूप से विचार में नहीं लिया गया है, दिलायी गयी राशि अपर्याप्त है, जबकि विद्वान अपीलार्थी-बीमा कम्पनी का निवेदन है कि उनके द्वारा जो बीमा पॉलिसी जारी की गयी थी, उसके अनुसार आहत बीमित नहीं था, इस कारण से अपीलाधीन निर्णय अपास्त होने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि जब तक विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित नहीं हो, तब तक “अधिनियम-1923” की धारा-30 के प्रावधानों के अनुसार अपील पोषणीय नहीं है, इस निर्णय के सुसंगत पैरा संख्या-9, 10, 11 तथा 12 निम्नानुसार है—

9. At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a



claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.

10. The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

वर्तमान मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त प्रतिकर राशि की गणना की गयी है। बीमा कम्पनी की यह आपत्ति रही थी कि आहत पॉलिसी के तहत कवर नहीं होता है, लेकिन उसके दोनों प्रश्नों पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्यक रूप से विचार कर अपना निष्कर्ष दिया है, दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव में हो अथवा उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए मनमाना निर्णय दिया हो, ऐसी स्थिति अभिलेख पर नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, इस प्रकार न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था तथा अधिनियम-1923 की धारा-30 के अनुसार उपरोक्त दोनों अपीलें पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं।



तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2015 की पुष्टि करते हुए
उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस निर्णय
की प्रति के साथ पुनः प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J